दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित तिथि: 25 अगस्त, 2023

उदघोषित तिथि: 13 सितंबर, 2023

रि.या.(सि.) 5185/2023 और सि.वि.आ. 20232/2023, 25770/2023, 25823/2023, 25841/2023, 28895/2023, 29129/2023, 29133/2023, 29137/2023

सिलिका उदयोग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि.)6064/2023

गिल इंटरनेशनल लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि.)11205/2023 और सि.वि.आ. 43662/2023, 43663/2023

सिलिका इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

रि.या.(सि.)11285/2023 और सि.वि.आ.43896/2023.43897/2023

सिलिका उदयोग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>रि.या.(सि.)11286/2023 और सि.वि.आ. 43898/2023,43899/2023</u>

आम्रपाली सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य ..... प्रत्यर्थी

<u>याचीगण के लिए:</u> श्री पराग पी. त्रिपाठी और श्री जयंत के. मेहता, वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ श्री अमन नंदराजोग, श्री सुमीर सोधी, श्री वरुण तन्खा और श्री श्रीनिवासन रामास्वामी, मद 15 और 30 में अधिवक्तागण।

श्री उमंग गुप्ता, श्री तरंग गुप्ता और श्री वंश कपूर, मद 16 में अधिवक्तागण।

<u>प्रत्यर्थीगण के लिए:</u> श्री संदीप सेठी और श्री राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ श्री टी. सुंदर रामनाथन, श्री विवेक पांडे, सुश्री सुकन्या विश्वनाथन, सुश्री श्रेया सेठी, श्री विक्रम सिंह दलाल, सुश्री रिया

कुमारी, श्री दुष्यंत कौल, श्री दिग्विजय सिंह और सुश्री बियंका भाटिया, मद 15, 28 और 30 में प्र.-3, 4, 5 के लिए अधिवक्तागण।

श्री रवि प्रकाश, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री फरमान अली, सुश्री उषा जमनाल, श्री अमन रेवारिया, श्री. यशार्थ शुक्ला और सुश्री अस्तू खंडेलवाल, अधिवक्तागण और श्री हार्दिक बेदी, मद 15 और 30 में प्र.-1 और 2 के लिए स.प्ली.।

श्री वेदांश आनंद, मद 16 में प्र.-1 और 2 के लिए स.प्ली.।

श्री के.डी. शर्मा, मद 16 में प्र.-1 और 2 के लिए अधिवक्ता।

श्री टी. सुंदर रामनाथन, श्री विवेक पांडे, सुश्री सुकन्या विश्वनाथन और सुश्री बियंका भाटिया, मद 16 और 31 में प्र.-3, 4, 5 के लिए अधिवक्तागण।

श्री आशीष जैन, के.स.स्था.अधि. के साथ श्री गौरव कुमार, सुश्री अंकिता केडिया, अधिवक्तागण और श्री प्रजेश विक्रम श्रीवास्तव, मद 28 और 31 में प्र.-1 और 2 के लिए स.प्ली.।

श्री रमन कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री प्रवीन महाजन, श्री अभिनव और श्री कुणाल, मद 15 में हस्तक्षेपकर्तागण के लिए अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय मुख्य न्यायाधीश संजीव नरूला

निर्णय

संजीव नरूला, न्या.

रि.या.(सि.) 5185/2023 *(सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 सह पठित आदेश I नियम 10 के तहत प्रतिवाद के लिए)* **में सि.वि.आ. 25770/2023, 25823/2023, 25841/2023 और 28895/2023**

1. उसमें बताए गए आधारों और कारणों के लिए, आवेदनों की अनुमति है और आवेदक – तिरुपति एल.पी.जी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पनाम सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड, सुपर टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड, और एस.एम. एल.पी.जी. सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड

[*सामूहिक रूप से, "हस्तक्षेपकर्तागण"*] को रि.या.(सि.) 5185/2023 के पक्षकारों के रूप में रखा गया है। हस्तक्षेपकर्तागण को उनके अधिवक्ता द्वारा सुना गया और उनकी दलीलों पर भी विचार किया गया है।

2. तदनुसार, आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

रि.या.(सि.)5185/2023, रि.या.(सि.)6064/2023, रि.या.(सि.)11205/2023, रि.या.(सि.)11285/2023 और रि.या.(सि.)11286/2023

3. हम पांच परस्पर जुड़ी याचिकाओं का सामना कर रहे हैं जो तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ["ओ.एम.सी"] – हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ["एच.पी.सी.एल"], भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ["बी.पी.सी.एल"], और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ["आई.ओ.सी.एल"] द्वारा जारी निविदाएं आमंत्रित करने के नोटिस ["एन.आई.टी"] में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को चुनौती देती हैं। याचिकाकर्ताओं की शिकायत का सार यह है कि पात्रता शर्तें उनके स्वामित्व वाली प्रत्येक विनिर्माण इकाई की निविदा प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की क्षमता को अनुचित रूप से कम कर देती हैं। वे दावा करते हैं कि यदि इन खंडों को संशोधित या हटाया नहीं गया है, तो इसका उन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जो संभावित रूप से उन्हें बाजार से पूरी तरह से हटने के लिए मजबूर करेगा। दूसरी ओर, ओ.एम.सी निविदा के नियम और शर्तों को निर्धारित करने के अपने विशेषाधिकार को रेखांकित करके अपनी स्थिति को दृढ़ता से पुष्ट करते हैं।

वे उपानन अनुकूलन के व्यापक लक्ष्य के साथ इसके संबंध को स्पष्ट करते हुए प्रतिबंधों की शुरूआत को और तर्कसंगत बनाते हैं।

4. सभी पाँच याचिकाओं में उठाए गए विधिक और तथ्यात्मक मुद्दों की एकरूपता और अधिवक्ता के बीच मौखिक तर्कों के पारस्परिक पृष्ठांकन को देखते हुए, हम वर्तमान निर्णय के माध्यम से इन याचिकाओं को सामूहिक रूप से संबोधित करना उचित पाते हैं। अपनी चर्चा को सुव्यवस्थित करने और समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए, हम मुख्य रूप से रि.या.(सि.) 5185/2023 में निर्धारित तथ्यों का संदर्भ देंगे।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

5. 1 मई, 2016 को, भारत के प्रधान मंत्री ने पिछड़े वर्गों के परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे वर्गीकृत समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से एक परोपकारी दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति के रूप में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना ("पी.एम.यू.वाई") की शुरुआत की। प्राथमिक उद्देश्य इन परिवारों को, जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर थे, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित करना था। इस नीति के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एल.पी.जी. सिलेंडरों की अभूतपूर्व मांग हुई। इसे संबोधित करने के लिए, भारत सरकार ने तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर, देश भर के अधिक निर्माताओं को शामिल करने के लिए अभियान शुरू किया, जिससे लागत प्रभावी दरों पर सिलेंडरों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा

सके। पी.एम.यू.वाई. के तहत एल.पी.जी. सिलेंडरों की बढ़ती मांग को देखते हुए, ओ.एम.सी. ने मार्च, 2017 में एन.आई.टी. को जारी किया, जिसमें संबंधित मात्रा में एल.पी.जी. सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। इन एन.आई.टी. में कई नवीन प्रावधान शामिल थे, जैसे कि बाजारों का क्षेत्रीय वितरण, मूल्य सीमा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों ["एम.एस.ई."] आदि को विशेष वरीयता, ये सभी को भारी मांग का समर्थन करने के लिए बाजार में नए निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

6. सिलिका उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी सहयोगी कंपनियों, सिलिका इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और अमरपाली सिलिंडर्स प्राइवेट लिमिटेड, को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत 'छोटे उद्यमों' के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे मुख्य रूप से देश भर में स्थित विभिन्न विनिर्माण इकाइयों के माध्यम से एल.पी.जी. गैस सिलेंडर के निर्माण और विक्रय के व्यवसाय में शामिल हैं। विशेष रूप से, इनमें से प्रत्येक इकाई पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ["पी.ई.एस.ओ"] और भारतीय मानक ब्यूरो ["बी.आई.एस"] दोनों से स्वतंत्र प्रमाणन रखती है। संक्षेप में, प्रत्येक इकाई एक स्व-निहित कारखाने के रूप में कार्य करती है। हालाँकि, याचीगण द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले एल.पी.जी. सिलेंडरों का एक सीमित बाजार है; उन्हें केवल भारत में तीन प्राथमिक ओ.एम.सी. अर्थात् बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. और आई.ओ.सी.एल. को

बेचा जा सकता है। इसका मतलब है कि पूरा सिलेंडर बाजार इन तीन इकाईयों तक ही सीमित है।

7. 2017 एन.आई.टी. में उल्लिखित विशेष प्राथमिकताओं ने याचीगण जैसे संभावित विक्रेताओं के बीच एक वास्तविक अपेक्षा को बढ़ावा दिया, जिन्होंने अनुमान लगाया कि ओ.एम.सी. उनकी नीति के अनुरूप रहेंगे। इस विश्वास से प्रेरित होकर, याचीगण ने अतिरिक्त विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किए और इनमें से प्रत्येक इकाई के लिए बी.आई.एस. और पी.ई.एस.ओ. लाइसेंस भी प्राप्त किए। सिलिका उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 26 फरवरी, 2019 को ओ.एम.सी. द्वारा जारी निविदाओं के तहत आपूर्ति ऑर्डर सुरक्षित करने के इरादे से सम्मिलित किया गया था। याचीगण की अपेक्षाएँ तब मान्य प्रतीत हुईं जब मार्च 2019 में, ओ.एम.सी. ने 2017 में शुरू किए गए विशेष प्रावधानों वाले एन.आई.टी. जारी किए।

8. हालांकि, उपरोक्त एन.आई.टी. को अप्रत्याशित रूप से रद्द कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को काफी नुकसान हुआ। प्रभाव दो गुना थे: उनकी नव स्थापित विनिर्माण इकाइयों की निष्क्रियता और उनके प्रतिष्ठानों के लिए प्राप्त ऋणों पर जमा ब्याज। फिर भी, नवंबर, 2019 में ओ.एम.सी. द्वारा नए एन.आई.टी. जारी करने से कुछ राहत मिली और याचीगण ने निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्दिष्ट संख्या में सिलेंडरों के उत्पादन के लिए अनुबंध प्राप्त

किए। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त एन.आई.टी. में 2017 एन.आई.टी. में पेश किए गए कुछ अधिमानी खंडों का अभाव था।

9. इसके बाद, 31 मार्च, 2023 को ओ.एम.सी. ने 14.2 किलोग्राम (इसके पश्चात, "मार्च 2023 एन.आई.टी") वजन वाले उच्च तन्यता शक्ति वाले एल.पी.जी. सिलेंडरों की खरीद के लिए नई निविदाएं जारी कीं। इन एन.आई.टी. में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के तहत, सहयोगी कंपनियों सहित सामान्य व्यवसाय स्वामित्व या प्रबंधन वाली सभी विनिर्माण इकाइयों को एक ही बोली लगानी होगी। इसलिए, याचीगण जैसे विक्रेताओं को उनकी प्रत्येक विनिर्माण इकाई के माध्यम से अलग-अलग बोलियां जमा करने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया है।

10. व्यथित, सिलिका उद्योग इंडिया प्रा. लिमिटेड ने उपरोक्त पात्रता शर्त पर आपत्ति जताते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका [रि.या.(सि.) 5185/2023] दायर की। उक्त याचिका में अंतरिम उपाय के रूप में 24 अप्रैल, 2023 को नोटिस जारी करते हुए, अंतिम परिणाम के अधीन, सिलिका उद्योग इंडिया प्रा.लि. लिमिटेड को अपनी सभी इकाइयों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

रि.या.(सि.) 5185/2023 दाखिल करने के बाद का घटनाक्रम

11. सिलिका उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समानता का दावा करते हुए, एक अन्य याचिकाकर्ता, गिल इंटरनेशनल लिमिटेड ने मार्च 2023 एन.आई.टी. में

शामिल प्रतिबंधात्मक पात्रता मानदंडों को आक्षेपित करते हुए रि.या.)सि. (6064/2023 दायर की, और अपनी स्वतंत्र विनिर्माण इकाई के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मांगी। **इस बीच, ओ.एम.सी. के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए,** चार एल.पी.जी. गैस सिलेंडर निर्माताओं ने रि.या.)सि. (5185/2023 में उचित आवेदन]सि.वि.आ.25770/2023, 25823/2023, 25841/2023 और 28895/2023] दायर करके हस्तक्षेप करने की मांग की।

12. जबकि रि.या.(सि.) 5185/2023 और रि.या.(सि.) 6064/2023 में न्यायनिर्णयन लंबित थे, ओ.एम.सी. ने 3 अगस्त, 2023 को एन.आई.टी. का एक नया सेट प्रकाशित किया [जिसे "अगस्त 2023 एन.आई.टी." के रूप में संदर्भित किया गया], जिसमें समान स्वामित्व/प्रबंधन वाली विनिर्माण इकाइयों को निविदा के लिए अलग-अलग बोलियां देने से वंचित करने की बात दोहराई गई। इसने मुकदमेबाजी का एक और दौर शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जहां सिलिका उद्योग प्राइवेट लिमिटेड ने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर तीन रिट याचिकाएं रि.या.(सि.) 11205/2023, रि.या.(सि.) 11285/2023 और रि.या.(सि.) 11285/2023 दायर कीं जिसमें उपरोक्त पात्रता मानदंडों को अभिखंडित करने की मांग की गई।

<u>पक्षकारगण की दलीलें</u>

<u>याचीगण की ओर से</u>

13. याचीगण का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पराग पी. त्रिपाठी और श्री जयंत के. मेहता ने उपरोक्त शर्त को बातिल करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए:

13.1. नए प्रस्तुत किए गए प्रावधान मनमाने हैं और उनमें विचारशील विचार-विमर्श का अभाव है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित पिछली नीतियों के आलोक में, पी.एम.यू.वाई. के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए कई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की गई। यह एक अच्छी तरह से स्थापित उम्मीद के साथ किया गया था कि अचानक नीति में बदलाव नहीं होगा जिससे निर्माताओं को अनुचित झटका लगता है। इस तरह के अचानक नीतिगत बदलाव न केवल निर्माताओं पर गंभीर कठिनाइयों को अधिरोपित करेंगे, बल्कि संभावित रूप से उन्हें पूरी तरह से बाजार से बाहर कर सकते हैं।

13.2. भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले पी.ई.एस.ओ. ने एकीकृत स्वामित्व के तहत एक ही परिसर के भीतर कई एल.पी.जी. सिलेंडर निर्माण इकाइयों के मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श किया है और उनका समाधान किया है। उनके रुख के परिणामस्वरूप एक ही स्थान पर कई एल.पी.जी. सिलेंडर निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। सविरोध निविदा शर्तें पी.ई.एस.ओ. के दिशानिर्देशों के साथ असंगत हैं, जो दो मंत्रालयों (पी.ई.एस.ओ. की देखरेख करने वाले पेट्रोलियम

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओ.एम.सी. को नियंत्रित करने वाले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा अपनाए गए रुख के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास को रेखांकित करती हैं।

13.3. एल.पी.जी. सिलेंडर बाजार की विशेषता एक अल्पविकसितता है, जिसमें केवल तीन खरीदार उपापन मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। एल.पी.जी. निर्माता मूल्य पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते क्योंकि निर्धारित न्यूनतम दर से नीचे की कोई भी बोली उन्हें स्वतः ही अयोग्य बना देती है। नतीजतन, उनकी बोलियों को ओ.एम.सी. द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा का पालन करना चाहिए। क्रेता-नियंत्रित निविदा प्रक्रिया को देखते हुए, याचीगण जैसे बोलीदाता मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय, प्रतिस्पर्धा प्रत्येक बोलीदाता को आवंटित आदेशों की मात्रा पर निर्भर करती है। एल. पी. जी. सिलेंडर बाजार में इस व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय द्वारा ***राजस्थान सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य*** में भी मान्यता दी गई थी, जिसमें यह देखा गया था कि केवल प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की आशंका पर निविदा शर्तों को सम्मिलित करना अस्वीकार्य है।

13.4. बाजार के क्षेत्रीय वितरण की ओ.एम.सी. की नीति ने कई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, जैसा कि याचीगण जैसी इकाईयों के साथ देखा गया है। विवादास्पद प्रावधान अब साझा स्वामित्व बाधाओं के कारण इन इकाइयों को गैर-व्यवहार्य बनाने का जोखिम उठाते हैं। नए बाजार प्रवेशक, जो

ऋण-आधारित निवेश पर कई इकाइयाँ स्थापित करते हैं, उन्हें एक इकाई द्वारा से लाभप्रदता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। इस न्यायालय द्वारा ***तिरुपति सिलिंडर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*** मामले में क्षेत्रीय विभाजन नीति के पीछे के तर्क पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया था। ओ.एम.सी. के कार्य किसी भी स्पष्ट सार्वजनिक हित के अनुरूप नहीं हैं और बताए गए उद्देश्य के लिए असमान प्रतीत होते हैं। साझा निदेशक या शेयरधारकों के आधार पर बोली भागीदारी को सीमित करना, खरीद प्रक्रिया की दक्षता से समझौता करता है, संभावित रूप से योग्य बोलीदाताओं के पूल को आधा कर देता है।

13.5. विवादित प्रावधानों की शुरूआत प्रतिस्पर्धा-विरोधी बाधाएं प्रस्तुत करती है, जो नए निर्माताओं के प्रवेश में बाधा डालती है और इस प्रकार, विधिक रूप से असमर्थनीय है। याचीगण को 19 अप्रैल, 2023 को दिए गए उनके जवाब में आक्षेपित निविदा शर्त पर आपत्ति जताते हुए बी.पी.सी.एल. ने 29 अक्टूबर, 2021 को जारी मॉडल निविदा दस्तावेज का उल्लेख किया, जिसमें इसी तरह का 'हितों का टकराव' खंड था। हालाँकि, इस खंड का उल्लेख वस्तुओं की खरीद के लिए नियमावली, 2017 में भी पाया गया, लेकिन 2019 में जारी एन.आई.टी. में आसानी से इसकी अवहेलना की गई। गैस सिलेंडर बाजार की अनूठी प्रकृति और

राजस्थान सिलेंडर्स (पूर्वोक्त) में हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए, साझा हिस्सेदारी वाली इकाइयों पर इस प्रतिबंध को नहीं लगाया जाना चाहिए।

13.6. ओ.एम.सी. की कार्रवाई, अनुचित, तर्कहीन और मनमाना होने के कारण, भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के विचार को पराजित करता है और प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

13.7. आक्षेपित स्थिति छोटे या उभरते हुए निर्माताओं को नुकसान पहुंचाती प्रतीत होती है, जो प्रमुख बाजार खिलाड़ियों का पक्ष लेते हैं, जिससे बाद वाले को अनुचित लाभ हो सकता है। यदि आपूर्ति की जाने वाली मात्रा को समान रूप से वितरित करने का इरादा था, जैसा कि ओ.एम.सी. द्वारा दर्शाया गया है, तो वे कई विनिर्माण इकाइयों वाली संस्थाओं के लिए क्षमता-आधारित प्रतिबंध लगा सकते थे, न कि उन्हें निविदा प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर कर सकते थे। यह देखते हुए कि अगस्त 2023 एन.आई.टी. में मूल्य खोज शामिल नहीं है, और सभी भाग लेने वाली संस्थाएं निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर बोली लगाएंगी, 'शक्ति की एकाग्रता' का तर्क अच्छा नहीं है।

ओ.एम.सी. और हस्तक्षेपकर्तागण की ओर से

14. श्री संदीप सेठी और श्री राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्कों को आगे बढ़ाते हुए ओ.एम.सी. के निर्णयों का जोरदार बचाव कियाः

14.1. *बाजार संचालित नीति समायोजन:* आक्षेपित निविदा शर्तों के लिए अंतर्निहित प्रेरणा मौजूदा बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति और घाटे की मांग के बीच चिह्नित असमानता है। उपानन को अनुकूलित करने और सभी विनिर्माण इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक इकाई को व्यक्तिगत बोली से प्रतिबंधित करने की शर्त पेश की गई थी। यह देखते हुए कि विनिर्माण इकाइयाँ एलपीजी सिलेंडरों की घटती आवश्यकता से संज्ञान हैं, याचीगण के 'वैध अपेक्षा' के दावे में योग्यता का अभाव है। वे ओ.एम.सी. को पहले की नीति का लगातार पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से जब उपानन रणनीतियाँ बाजार की गतिशीलता के जवाब में विकसित होती हैं।

14.2. *2023 एन.आई.टी. के तहत विशिष्ट उपानन विनिर्देश:* मार्च और अगस्त 2023 एन.आई.टी. आई.एस. 15914 मानकों के अनुरूप 'उच्च घनत्व वाले इस्पात'/'उच्च शक्ति वाले इस्पात' के उपानन से संबंधित हैं, जबकि पहले की निविदाओं में बड़ी मात्रा में नियमित इस्पात की आपूर्ति की मांग की गई थी। उच्च तन्यता इस्पात के लिए पी.ई.एस.ओ. और बी.आई.एस. लाइसेंस प्रक्रिया 2017 और 2019 में जारी एन.आई.टी. के तहत आवश्यक इस्पात की तुलना में अधिक कठोर है। इसके अलावा, पिछली निविदाओं के विपरीत, मार्च 2023 एन.आई.टी. ने प्रस्तुत बोलियों के आधार पर मूल्य खोज को शामिल किया। इस प्रकार, सर्वोत्तम संभव मूल्य सुनिश्चित करने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करने और संबंधित

इकाइयों द्वारा बोली-धांधली/दुरभिसंधि को रोकने के लिए, ओ. एम. सी. एस. ने आक्षेपित शर्त निर्धारित की।

14.3. *बाजार के एकाधिकार को रोकना:* आपूर्ति-मांग के स्पष्ट असंतुलन को देखते हुए, बोलीदाताओं को अपनी प्रत्येक इकाई का अलग से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप प्रतिभागियों की अतिसंतृप्ति हो सकती है। यह संभावित रूप से मुट्ठी भर सिलेंडर निर्माताओं को सुविधा प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से कई परिचालन इकाइयों वाले, ऑर्डर के अनुपातहीन हिस्से पर एकाधिकार करने के लिए, एक प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के सार को कम कर सकता है।

14.4. *सरकारी दिशानिर्देशों और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ संरेखण:* संविधान के अनुच्छेद 39 (ग) के तहत उत्पादन के साधनों और धन के संकेन्द्रण को रोककर आर्थिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए बाध्य है। उपानन अनुबंध भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के साथ निर्बाध रूप से संरेखित होते हैं, और एक नीतिगत विचार है जिसका उल्लेख आम तौर पर मॉडल निविदा दस्तावेज़ सहित कई सार्वजनिक निविदाओं में पाया जाता है।

14.5. *निविदा हस्तक्षेप में न्यायिक प्रतिबंध:* निविदा शर्तों और नीतियों से संबंधित मामलों में न्यायालय का कार्यक्षेत्र स्वाभाविक रूप से सीमित है। स्पष्ट

मनमानेपन, स्पष्ट अवैधता या स्पष्ट द्वेष के उदाहरणों को छोड़कर, न्यायालय को आम तौर पर ऐसे नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

15. हस्तक्षेपकर्तागण के अधिवक्ता ने ओ.एम.सी. की ओर से पहले उल्लिखित दलीलों का समर्थन किया। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिलिका उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास उच्च तन्यता ताकत वाले इस्पात एल.पी.जी. सिलेंडरों के निर्माण के लिए अपेक्षित पी.ई.एस.ओ. और बी.आई.एस अनुमोदन का अभाव है और इसलिए, पात्रता मानदंडों को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

16. दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, अब हम अपना ध्यान विवादित खंडों की ओर केन्द्रित करते हैं। सभी एन.आई.टी. में आक्षेपित स्थिति लगभग समान होने के कारण, सुविधा के लिए, बी.पी.सी.एल. के मार्च 2023 एन.आई.टी. के खंड 6 (क) में निहित शर्त निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की गई हैः

> *"(क) मूल्य बोली निवेदनः*
> *बोलीदाता की परिभाषा इकाई के रूप में है, जिसके पास अद्वितीय पैन है।*
> *एक बोलीदाता एक विशेष बोली प्रक्रिया में केवल एक बोली प्रस्तुत करेगा।*

<u>यदि किसी नियंत्री कंपनी के पास एक से अधिक स्वतंत्र विनिर्माण इकाइयाँ हैं या एक से अधिक इकाइयाँ हैं जिनके पास सामान्य व्यवसाय स्वामित्व/प्रबंधन है, तो केवल एक इकाई को उद्धृत करना चाहिए।</u>

इसी तरह के प्रतिबंध निकट संबंधी सहयोगी कंपनियों पर भी लागू होंगे। बोलीदाता की सहयोगी/सहयुक्त/संबद्ध संस्था द्वारा उसी निविदा में भाग लेने या आवेदन करने पर बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

एक बोलीदाता जो एक से अधिक बोली प्रस्तुत करता है, विशेष बोली में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर देगा।

उपरोक्त के संबंध में, एक व्यक्ति में स्वत्वधारिता / साझेदारी फर्म / लिमिटेड देयता साझेदारी / प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड कंपनी / सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत फर्म / वैधानिक निकाय / कोई अन्य विधिक इकाई, जैसा भी मामला हो, शामिल होगी, और यदि कोई व्यक्ति नीचे दिए गए दो प्रारूपों में से किसी एक में बोली लगाता है, तो उसे एक विशेष बोली में एकाधिक बोलियाँ प्रस्तुत करने वाला माना जाएगा:

I. व्यक्तिगत या स्वामित्व प्रारूप और/या

II. एक साझेदारी या व्यक्तियों के संगठन का प्रारूप और/या

III. एक कंपनी प्रारूप

जिससे,

- *इस उद्देश्य के लिए एक कंपनी में कोई भी कृत्रिम व्यक्ति शामिल होगा चाहे वह भारतीय विधि के तहत या किसी अन्य देश का हो।*

- *किसी व्यक्ति को साझेदारी प्रारूप में या व्यक्तियों के संघ के प्रारूप में बोली लगाने वाला माना जाएगा यदि वह उस फर्म का भागीदार है जिसने बोली जमा की है या व्यक्तियों के किसी संघ का सदस्य है जिसने बोली प्रस्तुत की है।*
- *किसी व्यक्ति को कंपनी प्रारूप में बोलीदाता माना जाएगा यदि वह व्यक्ति:*

  i. बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी की वोटिंग शेयर पूंजी का 10% (दस प्रतिशत) से अधिक, या

  ii. उस कंपनी का निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक है जिसने बोली प्रस्तुत की है, या

  iii. मतदान हिस्सेदारी पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक (दस प्रतिशत) रखता है और/या एक निदेशक और/या एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक है उस कंपनी की नियंत्री कंपनी जिसने बोली प्रस्तुत की है।

यदि संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित लाइसेंस, यानी पी.ई.एस.ओ. अनुमोदन या बी.आई.एस. लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो बोलीदाता के साथ अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।"

[जोर दिया गया]

<u>एल.पी.जी. सिलेंडरों की मांग में कमी</u>

17. किसी भी सार्वजनिक उपानन प्रक्रिया का प्राथमिक सिद्धांत निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। आक्षेपित खंड, जिसका उद्देश्य खेल के मैदान को समतल

करना है, किसी भी इकाई को भाग लेने से नहीं रोकता है; इसके बजाय, यह बोलियों की संख्या को सीमित करता है जो वे प्रस्तुत कर सकते हैं। ये प्रतिबंध किसी एकल इकाई या सामान्य स्वामित्व या प्रबंधन वाली संस्थाओं को कई बोलियाँ प्रस्तुत करके अनुचित रूप से लाभ उठाने से रोकते हैं और इस प्रकार, बाज़ार पर एकाधिकार स्थापित करते हैं।

18. आइए अब हम ओ.एम.सी. के आक्षेपित निर्णय के अंतर्निहित तर्क का विश्लेषण करें। उनका तर्क है कि ये खंड आपूर्ति और मांग की गतिशीलता को संतुलित करने, कई विनिर्माण इकाइयों वाली संस्थाओं द्वारा बाजार के एकाधिकार को रोकने और विविध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। यह परिप्रेक्ष्य दर्शाता है कि यह निर्णय बाजार के अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय उपाय है। उन्होंने निम्नलिखित ऐतिहासिक आंकड़ों के माध्यम से एल.पी.जी. गैस सिलेंडरों की मांग में गिरावट को प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट संदर्भ भी प्रस्तुत किया हैः 2017 में, 5.5 करोड़ इकाईयों सिलेंडर के लिए 17.54 करोड़ इकाईयों की पेशकश के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। इसी तरह, 2019 में 3.16 करोड़ इकाइयों के लिए जारी एन.आई.टी. ने 1 करोड़ इकाइयों के लिए बोलियां आकर्षित कीं। इसके बिल्कुल विपरीत, मार्च 2023 में एन.आई.टी. ने तुलनात्मक रूप से मामूली 10 लाख इकाइयों की मांग की, जबकि व्यापक बाजार आकलन 14.2 किलोग्राम सिलेंडरों के लिए लगभग 1.80 करोड़ की मांग का संकेत

देते हैं। समझने में आसानी के लिए, आपूर्ति-मांग अनुपात को प्रदर्शित करने वाले मुख्य आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में समाहित किया गया हैः

एल.पी.जी. सिलेंडरों की वर्षवार उपानन (लाख में)

ओ.एम.सी.	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आई.ओ.सी.एल	107.4	113.36	138.82	146.75	190.47	188.32	205.04	244.4	95.6	82.7	101.44	60.77	80
बीपीसीएल	46.36	50.91	20.91	83.2	76.95	143.44	103.64	134.64	76.93	45.53	57.6	55	55
एचपीसीएल	64.34	51.07	51.07	75.34	85.35	109.05	126.84	130.53	85.98	54.76	60.57	24.97	45
कुल मांग	218.1	215.34	215.34	305.29	352.77	440.81	435.64	509.57	258.51	182.99	219.61	140.74	180

19. उपरोक्त प्रस्तुत आंकड़े निर्विवाद रूप से हाल के वर्षों में एल.पी.जी. सिलेंडर की घटती मांग को रेखांकित करते हैं। यह गिरावट विशेष रूप से निविदा की गई इकाइयों की संख्या और वास्तव में प्राप्त हुईं बोलियों के बीच की असमानता पर प्रकाश डाला गया, जो एक अधिक आपूर्ति की स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश करती हैं। इसके अलावा, एल.पी.जी. सिलेंडर के जीवनकाल को देखते हुए आमतौर पर - 15 से 20 साल के बीच इसका कारण यह है कि नए सिलेंडर की आवश्यकता में - गिरावट जारी रहेगी क्योंकि मौजूदास्टॉक प्रचलन में रहता है। यह घटती मांग मार्च और अगस्त 2023 एन.आई.टी. में 'हितों के टकराव' खंड की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। यह संभावित रूप से अलगअलग विनिर्माण -

इकाइयों या संबद्ध संस्थाओं से कई बोलियों के साथ निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम संस्थाओं द्वारा बाजार एकाधिकार के जोखिम को कम करेगा। एल.पी.जी. सिलेंडरों की लंबी उम्र के कारण आपूर्ति की मांग और भविष्य में और भी अधिक असंतुलन की संभावना के साथ, खरीद प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में, यदि एक ही स्वामित्व या प्रबंधन के तहत कई इकाइयों को अलगअलग बोली लगाने की अनुमति दी जाती है-, तो इससे उन्हें असमान रूप से लाभ हो सकता है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान वितरण के सिद्धांतों को विफल किया जा सकता है। आक्षेपित खंड, संक्षेप में, कुछ चुनिंदा इकाईयों के बजाय समग्र रूप से बाजार के हितों की रक्षा करता है। यह दृष्टिकोण बाजार की अखंडता को बनाए रखने और सभी प्रतिभागियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के व्यापक सिद्धांत के साथ संरेखित करता है। इस प्रकार, प्रतिबंध लागू करने के ओ.एम.सी. के निर्णय में काफी योग्यता है।

अल्पविकसितता और बाजार की गतिशीलता

20. याचिकाकर्तागण ने एल.पी.जी. सिलेंडर बाजार की अल्पविकसित विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, जो अनिवार्य रूप से तीन प्राथमिक खरीदारों एच.पी.सी.एल, बी.पी.सी.एल. और आई.ओ.सी.एल. के आसपास केंद्रित है। हालाँकि यह बाजार संरचना अपनी स्वयं की चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन यह ध्यान देना उचित है कि मार्च और अगस्त 2023 में एन.आई.टी. में निर्धारित शर्तें

प्रतिस्पर्धा को दबाने की इच्छा से प्रेरित नहीं हैं, बल्कि एक ही निर्माता के हाथों में बाजार शक्ति के अनुचित एकाग्रता को रोकने के लिए प्रेरित हैं। एक विविध आपूर्तिकर्ता आधार को बढ़ावा देने का उद्देश्य एक अल्पविकसित बाजार द्वारा उत्पन्न आंतरिक चुनौतियों के प्रति संतुलन के रूप में काम कर सकता है। एकल इकाई द्वारा बाजार के वर्चस्व को हतोत्साहित करके, निविदा शर्तों को सीमित क्रेता विकल्पों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया लगता है, जिससे सभी बाजार सहभागियों के लिए अधिक समान अवसर तैयार होते हैं। ।

आक्षेपित पात्रता शर्त की मनमानेपन और अनुचितता पर

21. किसी भी विधिक विश्लेषण की आधारशिला यह निर्धारित करना है कि क्या विचाराधीन कार्रवाई या खंड मनमाना है। आक्षेपित खंड, हालांकि पिछली नीतियों से अलग है, मनमाना या अनुचित नहीं है। इसका उद्देश्य वर्तमान बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होते हुए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बोली प्रक्रिया में विविध भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह पात्रता शर्त नए और छोटे निर्माताओं के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय है। कई विनिर्माण इकाइयों वाली बड़ी इकाईयों को कई बोलियों के साथ निविदा भरने से प्रतिबंधित करके, यह खंड नई इकाईयों को निविदा प्राप्त करने के लिए एक उचित अवसर का प्रयास करता हैं। इस परिदृश्य को माना जा सकता है, और याचिकाकर्तागण जैसे कुछ लोगों के लिए दुर्भर साबित हो सकता है, यह किसी विशेष इकाई को अलग नहीं करता है; बल्कि,

यह सार्वभौमिक रूप से उन सभी बोलीदाताओं पर लागू होता है जो निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप हैं। वास्तव में 29 अक्टूबर, 2021 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वस्तु की खरीद के लिए मॉडल निविदा दस्तावेज में भी एन.आई.टी. में शामिल किए जाने वाले इसी तरह के 'हितों के टकराव' खंड का उल्लेख किया गया है। यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के आक्षेपित स्थिति के उद्देश्य को मजबूत करता है। इसलिए, हम इसे अनुचित या मनमाना नहीं पाते हैं।

22. ***राजस्थान सिलेंडर*** (पूर्वोक्त) में निर्णय, जिसमें एल.पी.जी. सिलेंडर बाजार में अल्पविकसितता की अवधारणा पर चर्चा की गई थी, गुटबंदी के संदर्भ में दुस्संधि और बोली-धांधली पर अधिक केंद्रित है, जो वर्तमान याचिकाओं का विषय नहीं है और इस प्रकार, एक अलग प्रासंगिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शीर्ष न्यायालय की टिप्पणियों से याचिकाकर्तागण के मामले में सहायता नहीं मिलेगी। आक्षेपित खंड की वैधता की जांच करने में, न्यायालय को याचिकाकर्तागण जैसी इकाईयों के विशिष्ट वाणिज्यिक हितों के खिलाफ व्यापक सार्वजनिक और बाजार हितों को तौलना चाहिए।

<u>वैध अपेक्षा का सिद्धांत</u>

23. 'वैध अपेक्षा' का सिद्धांत इस धारणा का प्रतीक है कि जब कोई सार्वजनिक प्राधिकरण किसी निश्चित वादे या व्यवहार को स्थापित करता है, तो प्रभावित

पक्षकारों के बीच एक उचित प्रत्याशा उत्पन्न होती है कि यह वादा या व्यवहार जारी रहेगा। यह अपेक्षा व्यावसायिक संदर्भ में विशेष रूप से प्रमुख हो जाती है, जहां उद्यम अक्सर दीर्घकालिक निवेश और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए सार्वजनिक नीति की स्थिरता और पूर्वानुमेयता पर निर्भर करते हैं। हालाँकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वैधता सिद्धांत अपेक्षा निर्वात में काम नहीं करता है। इसे जनहित की व्यापक अनिवार्यताओं के खिलाफ विवेकपूर्ण तरीके से तौला जाना चाहिए। चल रहे विवाद के संदर्भ में, मौजूदा बाजार स्थितियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से, बाजार की गतिशीलता में ध्यान देने योग्य बदलाव, जिसमें एल.पी.जी. सिलेंडर की घटती मांग शामिल है। बाजार के एकाधिकार के हमेशा मौजूद जोखिम के साथ, ये कारक ओ.एम.सी. को अपने मौजूदा नीतिगत ढांचे को अनुकूलित करने और विकसित करने के लिए एक सम्मोहक तर्क प्रदान करते हैं। हालांकि यह सच है कि व्यावसायिक संस्थाओं को एक स्थिर और सुसंगत नीतिगत वातावरण से लाभ होता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि नीतिगत ढांचे अपरिवर्तनीय निर्माण नहीं हैं। बल्कि, वे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनों को समायोजित करने या नए उभरते मुद्दों से निपटने के लिए लचीले और अनुकूल होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो शुरू में प्रत्याशित नहीं थे। यह अंतर्निहित लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि नीतिगत ढांचा न केवल

हितधारकों के एक विशेष वर्ग के हितों के लिए, बल्कि व्यापक समुदाय के कल्याण के लिए भी अनुकूल रहे।

प्रशासनिक नीतियों की गतिशील प्रकृति और निविदा निर्णयों में गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत

24. जब प्रशासनिक अधिकारियों के नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करने या उनमें हस्तक्षेप करने की बात आती है तो न्यायालय पारंपरिक रूप से संयम बरतते हैं। इस तरह के नीतिगत निर्णय अक्सर उन अधिकारियों की विशेषज्ञ समझ और विशेष ज्ञान में निहित होते हैं। जब तक कदाचार या सत्ता के दुरुपयोग का सबूत न हो, न्यायालय नीति-निर्माता निकाय के ज्ञान और विवेक का सम्मान करती हैं। वैध अपेक्षा का सिद्धांत प्रशासनिक निकायों को अपनी नीतियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं करता है, खासकर अगर ये परिवर्तन व्यापक सार्वजनिक हित में हैं। नीतियाँ गतिशील हो सकती हैं, नई परिस्थितियों और वास्तविकताओं के अनुकूल हो सकती हैं। प्रशासनिक निर्णय, विशेष रूप से सार्वजनिक उपानन से संबंधित निर्णय, नियमितता का अनुमान लेकर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे निर्णय व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए गहन विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब इस धारणा का दृढ़तापूर्वक खंडन किया गया हो, जो कि यहाँ मामला नहीं है।

24.1. *आर्थिक मामलों में न्यायिक प्रतिबंध:* आर्थिक नीतियों से जुड़े निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा सीमित है। न्यायालय प्रशासनिक निर्णयों पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करती हैं, बल्कि केवल तभी हस्तक्षेप करती हैं जब स्थितियाँ स्पष्ट रूप से मनमौजी, अनुचित, या विशेष रूप से किसी निश्चित इकाई को लाभ पहुँचाने के लिए तैयार की जाती हैं। ***आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ*** में, उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि उनकी वैधता की जांच करते हुए, आर्थिक मामलों को उनके जटिल प्रकृति के कारण अधिक छूट और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। आर्थिक मुद्दों से संबंधित विधि को बनाते समय या निर्णय लेते समय, प्रभारी निकाय के पास जटिल स्थिति के अनुकूल होने और प्रतिक्रिया देने के लिए जगह होनी चाहिए जिन चुनौतियों का स्पष्ट समाधान होना जरूरी नहीं है। ऐसे मामलों में, न्यायालयों को अपने "अल्प और अव्याख्यायित अनुभव" के साथ, विधायी या प्रशासनिक निर्णय को स्थगित करने के लिए अधिक इच्छुक होना चाहिए, जो अनुभवजन्य समझ पर आधारित है। ***बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) बनाम भारत संघ और अन्य,*** और ***श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** निर्णयों में, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए नियम बनाने वाले प्राधिकरण के परमाधिकार को स्वीकार करें जो कुछ निवेशित व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इस विचार की पुष्टि

करते हैं कि न्यायालयों को आम तौर पर आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि अधिकारों या सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन न हो।

24.2. *गैर-हस्तक्षेप की रूपरेखाएँ:* ***एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड***, ***यूफ्लेक्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य***, और ***सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एस.एल.एल.-एस.एम.एल. (संयुक्त उद्यम कंसोर्टियम) और अन्य*** जैसे कई मामले, मनमानेपन, तर्कहीनता, पक्षपात आदि के उदाहरणों को छोड़कर, प्रचलित आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए निविदा शर्तों को अधिकृत करने में सरकारी और अन्य विशेष निकायों की विशेषज्ञता के लिए न्यायिक सम्मान की आवश्यकता पर जोर देते हैं। ***तिरुपति सिलिंडर्स प्राइवेट लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में, विशेष रूप से एल.पी.जी. सिलेंडर उपानन से संबंधित मामला, न्यायालय ने नीतियों के बदलने पर हस्तक्षेप नहीं किया, इस बात पर जोर देते हुए कि व्यवसाय या लाभ में कथित कमी स्वचालित रूप से राज्य के निर्णयों को अनुचित नहीं बनाती है। हमारी राय में, भारत जैसी गतिशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक बदलाव, नीतिगत बदलाव और विभिन्न व्यावसायिक जोखिम आम हैं और व्यवसायों को ऐसी आकस्मिकताओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केवल यह तथ्य कि याचीगण को कुछ कठिनाइयों या लाभ में संभावित कमी का सामना करना पड़ सकता है, आक्षेपित निर्णय को पलटने की गारंटी नहीं देता है। जैसा कि ***तिरुपति सिलिंडर्स प्राइवेट लिमिटेड*** *(पूर्वोक्त)* में जोर

दिया गया है, जबकि भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत व्यवसाय करने के अधिकार की गारंटी देता है, यह 'लाभ का अधिकार' सुनिश्चित नहीं करता है।

वैकल्पिक प्रस्ताव और उनकी योग्यता

25. समान वितरण सुनिश्चित करने के साधन के रूप में आवंटन को सीमित करने का याचीगण का प्रस्ताव शायद एक और व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करता है। हालांकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि बाजार भागीदारी में साम्यता प्राप्त करना विभिन्न तंत्रों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। यहाँ ओ.एम.सी. द्वारा चुना गया दृष्टिकोण बाजार की स्थितियों की उनकी सूक्ष्म समझ का उत्पाद है, जो ऐतिहासिक आंकड़ों और भविष्य की चुनौतियों के विचारों से सूचित है। ओ.एम.सी. के लिए अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करना इस न्यायालय के दायरे में नहीं है जब तक कि उनका निर्णय मनमाना या अनुचित नहीं पाया जाता है। विशेष रूप से एल.पी.जी. सिलेंडर जैसे विशेष बाजार में निविदा शर्तों को तैयार करने की जटिलताओं को विषय-वस्तु में विशेषज्ञता रखने वालों पर छोड़ दिया जाता है। ओ.एम.सी., जो निविदा के वास्तुकार हैं, संभावित बाजार एकाधिकार और अनेक बोलियों की बारीकियों और प्रभावों को समझने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। इसलिए, जब तक अन्यथा साबित नहीं हो जाता है, यह ओ.एम.सी. को उन स्थितियों को स्थापित करना है जिनके तहत निविदा प्रक्रिया संचालित होती है, यह

सुनिश्चित करते हुए कि यह प्रमुख खिलाड़ियों के एक सीमित समूह द्वारा संभावित बाजार को घेरने के खिलाफ प्रतिस्पर्धी, कुशल और लचीला बना रहे।

<u>निष्कर्ष</u>

26. आर्थिक और नीतिगत निर्णय, विशेष रूप से सार्वजनिक उपनन से संबंधित, व्यापक कल्याण और निष्पक्षता सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होने चाहिए। इस संदर्भ में, 'हितों के टकराव' खंड का एक तर्कसंगत आधार एल.पी.जी. सिलेंडर बाजार की वास्तविकताओं में निहित प्रतीत होता है। मांग में गिरावट को देखते हुए न्यायसंगत वितरण के व्यापक उद्देश्य को देखते हुए, आक्षेपित खंड की शुरूआत मनमानी या अनुचित नहीं लगती है। इसके बजाय, यह निष्पक्षता और व्यापक-आधारित भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बाजार की बदलती गतिशीलता के अनुकूल होने के लिए एक जाँच किया गया उपाय प्रतीत होता है। इन परिवर्तनों के अनुकूल होने में याचीगण के सामने आने वाली चुनौतियों से न्यायालय के हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनते हैं। हालांकि इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक तंत्र मौजूद हो सकते हैं, इस मामले में तंत्र का चुनाव, ओ.एम.सी. द्वारा 'हितों के टकराव' खंड की शुरूआत, तर्कसंगत और सूचित प्रतीत होती है। इस खंड की शुरुआत में बाजार की वास्तविकताओं और एमएसई सहित आपूर्तिकर्ताओं के बीच समान वितरण सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखा गया। यह देखते हुए कि यह सुझाव देने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है

कि खंड मनमाना, भेदभावपूर्ण है, या दुर्भावनापूर्ण इरादे से पेश किया गया है, इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप का कोई ठोस कारण नहीं है। संक्षेप में, यहां जिस सिद्धांत की पुष्टि की गई है, वह यह है कि न्यायालयों को निविदाओं और नीतिगत निर्णयों से संबंधित मामलों में प्रशासनिक विवेकाधीन के प्रति संयम और सम्मान का प्रदर्शन करना चाहिए, जब तक कि स्थापित विधिक मानदंडों या सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन न हो।

27. पूर्वगामी कारणों से, वर्तमान याचिकाओं को लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दिया जाता है।

संजीव नरूला, न्या.

सतीश चंद्र शर्मा, मु.न्या.

13 सितंबर, 2023
डी.नेगी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*